जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 312 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 15 सितम्बर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'निवेशकों ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था डबल होगी। उन्होंने कहा कि, राजस्थान में विदेशी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोला जाएगा

जयपुर, 14 सितंबर। राजस्थान में उद्योग-धंधों की अपार संभावनाओं के चलते निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा पर गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर लौटने पर आज एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक उनका भव्य स्वागत किया गया। लोक कलाकारों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाडों, बैंड-बाजों के साथ पुष्प वर्षा के बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपार प्रेम, स्नेह और भरोसा देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी।

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि राइज़िंग राजस्थान के लिए इन्वैस्ट समिट की तरह ग्लोबल समिट होगा और 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नई दिल्ली में रोड शो होगा।**

जापान और उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद वापस लौटने पर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मु. मंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मु. मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा, जापान के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश के विषय में बहुत ही पॉज़िटिव प्रतिक्रिया दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के भरोसे से मुझे कार्य करने की ताकत मिलती है। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश करने के लिए पॉज़िटिव प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जापान की एक कंपनी ने तो राजस्थान के 15 हजार युवाओं को जापान में रोजगार तक देने का वादा भी कर दिया। ऐसे में राजस्थान में विदेशी भाषाओं की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही थीं सेबी चीफ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने शनिवार को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि माधवी ने 2017 से 2023 के बीच विदेशी फर्मों की लिस्टेड सिक्युरिटीज़ में निवेश किया था। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को पता था कि वह ऐसे समय में चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही थीं जब भारत चीन के साथ भू-राजनैतिक समस्या का सामना कर रहा है।

- **कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में पता था।**

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रैस में कहा कि सेबी प्रमुख चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही हैं और यह अभी भी चल रहा है उनके पास चीनी कम्पनियों की सनसनीखेज सूचनाएं हैं। खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह चीनी सामान भारत ला रही हैं।

खेड़ा ने माधवी से पूछा क्या उनकी और उनके परिवार की उन कंपनियों से कोई सांठगांठ है जिनके नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज़ पेपर्स में थे।

माधवी और उनके पति ने इन आरोपों पर कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है कि खेड़ा ने कहा कांग्रेस विपक्षी दल होने की जिम्मेवारी निभा रही है।

प्र.मंत्री मोदी के सी.जे.आई. के घर जाने पर न्यायविदों में भारी विवाद खड़ा हुआ

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **भाजपा के सम्बित पात्रा का तर्क है कि 2009 में जब तत्कालीन प्र.मंत्री मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी दी थी तब तत्कालीन सी.जे.आई. के.जी. बालाकृष्णन उसमें शामिल हुए थे, अब गणेश पूजा पर विवाद अनुचित है।**
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तर्क है कि प्रधानमंत्री का गणपति पूजा पर सी.जे.आई. के घर जाना व्यक्तिगत मसला हो सकता है, पर, उसका वीडियो बनाकर प्रचारित करना सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आघात है।**

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड ने नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई गणपति पूजा में जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जाने -माने वकीलों, रिटायर्ड जजों और विपक्षी नेताओं ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि पूजा में जाने की खबर को क्या सार्वजनिक किया जाना चाहिए था।

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने ऑन लाइन प्रचारित हो रही वीडियो क्लिप्स पर आश्चर्य जताया।

सिब्बल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते 50 साल से भी ज्यादा हो चुके है, ने सी.जे.आई. की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट किया लेकिन इस घटना के प्रचार पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को निजी कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है सी.जे.आई. का इरादा सार्वजनिक प्रचार का ना हो, पर ऐसे निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति उचित नहीं थी।

सिब्बल ने कहा कि इस घटना को लेकर जो बातें चल रही हैं उससे सुप्रीम कोर्ट की साख पर दाग लग सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी सी.जे.आई. के आवास पर हुई गणपति पूजा में शामिल हुए तथा एक वीडियो में सी.जे.आई. व उनकी पत्नी को मोदी का स्वागत करते हुए दिखाया गया। इस पर विपक्षी नेता व कानूनविद् तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे आर.एम. लोढ़ा ने कहा कि संवैधानिक रुप से "शक्तियों का पृथक्करण" (सैपररेशन ऑफ पावर्स) है और आमतौर पर न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच दूरी रखी जाती है।

उन्होंने कहा ऐसी मुलाकातों से न्यायपालिका की सार्वजनिक अवधारणा प्रभावित होती है, पर न्यायिक फैसलों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जज जो भी स्वतंत्र रुप से करना चाहता है वो करेगा। पर मेरी याददाश्त में यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री किसी सी.जे.आई. के सरकारी आवास पर गए हों।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा, यात्रा को सार्वजनिक बनाना गलत था। मेरे विचार से विज़िट को सार्वजनिक करना सही नहीं था। मुझे नहीं पता किसने किसे आमंत्रित किया था पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे विज़िट आम जनता की नज़र में न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। माथुर 2018 से 20121 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता इससे सी.जे.आई. के भावी फैसले प्रभावित होंगे पर इससे आम जनता में उनकी गलत छवि बनेगी। इससे गलत संदेश जा सकता है।"

शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है लोग एक दूसरे के घर जाते हैं मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री किसी के घर गए हैं या नहीं। दिल्ली व महाराष्ट्र सदन में कई जगहों पर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सी.जे.आई. के घर गए उन्होंने आरती की। हमें लगता है कि अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलेंगे तो जनता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अशोक गहलोत के सब्सिडी वादों के झूठे जाल में फंसे उद्योगपति

पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022 में "रिप्स पॉलिसी" की घोषणा तो की, लेकिन नीति बनाकर टैक्स छूट व सब्सिडी नहीं दी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 14 सितम्बर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में वोटबैंक साधने और अपनी सरकारी के लिए वाहवाही लूटने के लिए कई तरह की सब्सिडी देने का झांसा उद्योगपतियों को दिया था। इन घोषणाओं के झूठे जाल में फंसकर जिन कंपनियों ने करोड़ों रु. खर्च करके राजस्थान में कई प्लांट लगा दिए, उनमें से अधिकांश को उनकी सरकार ने सब्सिडी ही नहीं दी।

वर्ष 2022 में गहलोत सरकार ने राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) लागू करते समय निवेशकों को, जो टैक्स छूट व सब्सिडी राहत देने की घोषणाएं की थी, वह नहीं दी गई। क्योंकि रिप्स पॉलिसी 2022 में बनी, लेकिन इसके प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश ही गत 23 अगस्त 2024 को जारी किए गए। इस गाइडलाइन के मुताबिक सब्सिडी

- **अब 2 साल बाद भजनलाल सरकार ने "रिप्स" में सब्सिडी व छूट देने के लिए गत 23 अगस्त 2024 को प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके पूर्व किस कंपनी को कितनी राहत, कैसे दी जाएगी, इस संबंध में कोई गाइडलाइन तय नहीं थी।**
- **गहलोत सरकार ने "रिप्स" पॉलिसी की घोषणा के समय निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्ज़न चार्जेज़, लैंड टैक्स, विद्युत शुल्क, बाजार अथवा मंडी टैक्स के साथ ब्याज सब्सिडी, टर्म लोन में राहत, ग्रीन इन्सैन्टिव, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक सब्सिडी, इन्वैस्टमैंट सब्सिडी, क्लस्टर बैनिफिट समेत कई तरह की छूट देने के वायदे किए थे।**

पाने के लिए कम से कम 50 करोड़ तक का निवेश अनिवार्य रखा गया है। इसके अभाव में व्यापार विस्तार के लिए मौजूदा निवेश का 25 प्रतिशत से ज्यादा राशि लगानी होगी। या मौजूदा उद्योग की 20 प्रतिशत क्षमता बढ़ानी होगी।

अशोक गहलोत की सरकार ने जब "रिप्स" पॉलिसी की घोषणा की थी, तब निवेशकों से वादा किया गया था कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेव समाज के दिग्गज नेता एवं रामगढ़ विधायक ज़ुबेर खान का निधन

अलवर, 14 सितम्बर (निसं)। मेव समाज के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता एवं रामगढ़ से विधायक ज़ुबेर खान का शनिवार को इंतकाल हो गया वे करीब डेढ़ वर्ष से बीमार चल रहे थे। उन्होंने शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे अन्तिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही अलवर में कांग्रेस नेताओं सहित मेव समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें शनिवार शाम पांच बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

- **ज़ुबेर खान करीब डेढ़ वर्ष से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही मेव समाज एवं कांग्रेसजनों में शोक की लहर दौड़ गई।**

जुबेर खान ने 8वीं तक की पढ़ाई अलवर के माचडी गांव के पास बगड़ राजपूत स्कूल से की थी। इसके बाद अलवर शहर के नवीन सीनियर सेकेंडरी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जलजीवन मिशन में 22 हजार करोड़ रू. के ठेके, केवल 8-10 कम्पनियों को पूल बनाकर बांटे गए

गहलोत सरकार का पूल बनाने का मकसद था कि टैंडर भरने वाली कम्पनियों की संख्या कम से कम हो

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के टैंडरों में मिलजुल कर दरें भरने और अपनी मर्जी के लोगों को न्यूनतम दर पर लाकर काम देने का खेल गहलोत सरकार में बेशर्मी से चला। जल जीवन मिशन के लगभग 22 हजार करोड़ के ठेकों में केवल 8-10 कंपनियों ने काम आपस में बांट लिए और 27 से 42 प्रतिशत ऊंची दरें भर दीं जिनको तत्कालीन ए.सी.एस. पी.एच.ई.डी. सुबोध अग्रवाल ने आंख मींचकर अनुमोदित कर टेंडर वित्त विभाग को भेज दिए, वित्त विभाग के मंत्री खुद अशोक गहलोत थे। समाचार पत्रों में मामला छपने और पाली सांसद पी पी चौधरी द्वारा लोकसभा में उठाए जाने पर गहलोत को निविदाएं निरस्त करनी पड़ी थीं।

- **असल में गहलोत सरकार का इरादा था कि कम्पनियाँ कम से कम रहें और उन पर, जायज़-नाजायज़ दबाव डालकर तथा लालच का इस्तेमाल कर चहेती कम्पनी को ही काम दिलवाया जाए।**
- **ऐसा कहा जा रहा है कि पूल बनाने से ठेकेदारों को 2000 करोड़ रूपए की राशि अधिक मिली, जिसका उपयोग उन्होंने नेताओं और अफसरों को खरीदने में किया।**
- **यह मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की सी.ए.जी. ऑडिट और सी.बी.आई. जाँच होनी चाहिए तब ही साबित होगा कि गहलोत ने मेघा इंजीनियरिंग को काम दिलवाने के लिए पूल बनाने का खेल रचा था।**

अब प्रश्न उठता है कि पूल कैसे हो पाया और कैसे सिद्ध होता है कि गहलोत सरकार के समय पूल हुआ। ये खेल शुरू होता है इस बात से कि टैंडर भरने की योग्यता रखने वाली फर्में कम से कम हों जिससे उन पर जायज़, नाजायज़ दबाव और लालच का इस्तेमाल करके कामों का बंटवारा किया जाए। अगर ऐसे टेंडरों की ऑडिट हो तो पता चलेगा कि एक फर्म जिस टेंडर में न्यूनतम है और उसमें किसी एक आइटम की रेट 1 करोड़ ऑफर करती है तो उसी आइटम की रेट दूसरे टेंडर में (जिसमें पूल की अन्य फर्म न्यूनतम है) 1.5 करोड़ भर देती है।

ई.आर.सी.पी. का काम विशेष प्रकार का होने के कारण, एक तो इस तरह की इंफ्रा कंपनियां देश में कम ही हैं और तकनीकी योग्यता की शर्तें मेघा इंजीनियरिंग के मन माफिक रखने से विश्वराज कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनी भी क्वालीफाई नहीं कर पाई और क्या मालूम उस कंपनी ने दबाव में जानबूझकर पूरे कागज ही प्रस्तुत नहीं किए।

तीन पैकेजों में केवल दो फर्में, मेघा इंजीनियरिंग और रामकी इंफ्रा की दरें खुलीं और आश्चर्यजनक रूप से तीनों में से एक में भी रामकी इंफ्रा न्यूनतम नहीं आ पाई। इस तरह के प्रतिष्ठा पूर्ण प्रोजेक्ट के टैंडर की दरें जिस लापरवाही से रामकी इंफ्रा ने भरी हैं उसकी जांच अगर गहराई से होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने खाद्य तेलों की इम्पोर्ट ड्यूटी में 20 प्रतिशत वृद्धि की

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (वार्ता) सरकार ने विदेशों से मंगाये जाने वाले कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है, जिससे सस्ते तेलों के आयात पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

भारत के राजपत्र में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल्य सीमा शुल्क (बीसीडी) की दर शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है।

- **पाम ऑयल, रिफाइण्ड ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दी गई है।**

इसी तरह रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी थक हार कर आन्दोलन स्थल पर भी गयीं

पर अपने लम्बे राजनीति अनुभव के बावजूद डॉक्टरों से बातचीत का गतिरोध नहीं तोड़ पायीं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। अनुभवी तथा चतुर राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी ने, वर्तमान संकट का समाधान ढूंढने के लिए आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के केवल एक छोटे से ग्रुप को शाम को अपने घर बुलाकर डॉक्टरों के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया।

उन्होंने हर तरह से युवा डॉक्टरों को लुभाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भारी चिंता भी व्यक्त की। चूँकि, इन दिनों शहर में लगातार बारिश हो रही है, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को "नहीं भीगने" की सलाह दी।

ममता बनर्जी रवैया, मृत महिला डॉक्टर के प्रति उनकी बैरुखी के बिल्कुल विपरीत था, जब उन्होंने कहा कि लोगों को आंदोलन को भूल जाना चाहिए तथा उत्सव के मूड में आ जाना चाहिए क्योंकि, दुर्गापूजा निकट है। सुबह के समय वो डॉक्टरों से मिलकर उन्हें अपनी मीठी बातों से प्रभावित करना चाहती थी।

तथापि, मीटिंग हो नहीं पाई, क्योंकि, अंत में सरकार ने उस स्तर की पारदर्शिता की इजाज़त नहीं दी, जिसकी जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे थे। राज्य सरकार लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सहमत नहीं हुई तथा आंदोलनरत डॉक्टरों के वीडियोग्राफरों को समस्त कार्यवाही का वीडियो लेने की इजाज़त नहीं थी।

डॉक्टरों के केस को हैण्डल करने के राज्य सरकार के रवैये से भी जूनियर डॉक्टर नाखुश हैं। सरकार ने दावा किया है कि 29 लोग मरे हैं, जबकि, डॉक्टर इस दावे को गलत बता रहे हैं। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी के जो हताशा भरे प्रयास हैं। उनसे पता चलता है कि सरकार इस मामले में कितनी बुरी तरह से घिर चुकी है।

- **उन्होंने अपने मनाने और मनुहार के सभी तरीके अपनाये, "चार्म" का पूरा उपयोग किया, पर, डॉक्टरों को तोड़ नहीं पायीं।**
- **अन्ततोगत्वा, मु.मंत्री ममता बनर्जी व आन्दोलनकारी डॉक्टरों की बातचीत इसलिये टूटी, क्योंकि, इस पर सहमति नहीं बनी कि मु.मंत्री के निवास पर आयोजित बातचीत व बैठक की वीडियोग्राफी कौन-कौन करेगा, केवल सरकारी वीडियोग्राफर या साथ में आए आन्दोलनकारी डॉक्टरों के वीडियोग्राफर।**
- **सरकार किसी भी हालत में, आन्दोलनकारियों के वीडियोग्राफर को बैठक की वीडियोग्राफी करने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी।**

जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि राज्य की जनता को, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की कार्यवाही जानने का पूरा अधिकार है। दोनों तरफ से वीडियोग्राफी का अभाव मीटिंग की पारदर्शिता को खत्म कर देगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के संकट का समाधान निकालने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किया। वो आंदोलन स्थल पर गईं और आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से सीधे बात की।

उन्होंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वो उनकी वैध मांगों पर विचार करेंगी। उन्होंने डॉक्टरों से काम पर वापस आने को कहा। तथापि, डॉक्टरों ने अपनी इस मांग को दोहराया कि उनकी सभी पांचों मांगें माननी होंगी।

बाद में उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया और संकट का समाधान निकालने के लिए बातचीत करने को कहा। शुरू में डॉक्टरों ने मांग की कि सभी 30 प्रतिनिधियों को मीटिंग में शामिल होने की अनुमति देनी होगी। तथापि, बाद में डॉक्टर 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लाने की मामता बनर्जी की मांग से सहमत हो गए।

तथापि, शाम की मीटिंग में राज्य सरकार अपनी इस बात पर दृढ़ रही कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो कि मु.मंत्री के साथ मीटिंग के लिए डॉक्टर्स की एक शर्त थी।

मुख्यमंत्री के निवास पहुँचने पर डॉक्टरों को बताया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर वीडियोग्राफी कराने का आश्वासन दिया था, यह कहते हुए कि जनता को जानने का अधिकार है कि मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन, सरकार ने यह बात मानने से इन्कार कर दिया कि वीडियोग्राफी डॉक्टर्स के वीडियोग्राफर द्वारा की जाए। इसके बाद डॉक्टर्स ने भी मुख्यमंत्री आवास में आने से मना कर दिया।

अशोक गहलोत को आलाकमान ने "लॉलीपॉप" दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कांग्रेस हाई कमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को लॉलीपॉप थमाया है और वो भी भूपेन्दर सिंह हूडा के हस्तक्षेप के बाद, जिनके अशोक गहलोत के साथ बहुत निकट के

- **राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हरियाणा में कांग्रेस का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस मौके का फायदा उठाकर गहलोत बड़ा पद पाने की कोशिश करेंगे।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)